

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृषि - परिवर्तन का एक नया युग: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री द्वारा ‘एचपी ड्रीम्स अनलॉक्ड’ महोत्सव का उद्घाटन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। ‘यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का युग है। इस परिवर्तनकारी तकनीक के माध्यम से समाज में साक्षरता और समानता प्राप्त की जा सकती है। प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण और एआई भौगोलिक सीमाओं को पार करते हैं और धन, जाति या भाषा के भेद को मिटाते हैं। इसलिए, इस तकनीक में प्रत्येक भारतीय के विचारों को आकार देने की क्षमता है,’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। वह बांद्रा स्थित महबूब स्टूडियो में एचपी और इंटेल् द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ‘एचपी ड्रीम्स अनलॉक्ड’ महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में एचपी इंडिया की प्रबंध निदेशक इप्सिता दासगुप्ता, मुख्यमंत्री के सलाहकार कौस्तुभ धवसे, मार्केटिंग प्रमुख आकाश भाटिया, कानूनी एवं



ने विभिन्न स्तरों पर एआई को अपनाने की नीति शुरू की है। उन्होंने बताया, ‘यह तकनीक सभी के लिए खुली है, जिससे हर व्यक्ति अपने नवोन्मेषी विचारों को वास्तविकता में बदल सकता है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सहयोग से पहले ही एक डिजिटल



पहुँच सुनिश्चित करके एक कदम और आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है।’ उन्होंने यह भी बताया कि एआई अनुप्रयोगों ने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। हाल ही में पुणे में आयोजित एपी-हैकार्थोन का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि युवा

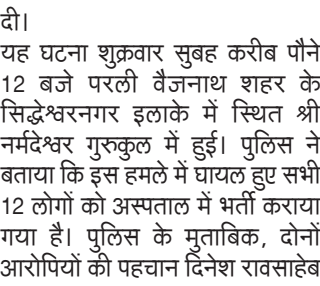
नवप्रवर्तकों ने ऐसे एआई मॉडल विकसित किए हैं जो वायु घटकों का विश्लेषण करके कीटों के संक्रमण का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और किसानों को पहले से सचेत कर सकते हैं - यह एक क्रांतिकारी नवाचार है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इस तरह के तकनीकी हस्तक्षेप फसलों के नुकसान को रोकेंगे, लागत कम करेंगे और कृषि में लाभप्रदता बढ़ाएंगे।’ उन्होंने आगे कहा कि एआई, ब्लॉकचेन और डिजिटलीकरण ने न केवल उद्योगों में क्रांति ला दी है, बल्कि शासन में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ाई है। स कार्यक्रम में देश भर के 40,000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से 40 उत्कृष्ट नवोन्मेषी पहलों को मान्यता और सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने समापन करते हुए कहा, ‘इन आशाजनक पहलों में समाज और अर्थव्यवस्था पर ठोस प्रभाव अनुप्रयोगों ने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। सरकार ऐसी परियोजनाओं में भागीदारी के लिए तैयार है जो नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बना सकें।’

परीक्षा से जुड़े विवाद को लेकर संगीत विद्यालय में घुसे दो लोग, 11 छात्रों को बेल्ट-डंडों से पीटा

बीड। महाराष्ट्र के बीड जिले के परली वैजनाथ शहर में एक संगीत स्कूल में परीक्षा से जुड़े विवाद को लेकर दो लोग स्कूल में घुसे और उन्होंने 11 छात्रों पर बेल्ट और डंडों से हमला किया और एक अन्य व्यक्ति को भी पीट दिया। यह जानकारी पुलिस ने शनिवार को

माने और बालू बाबूराव एकिलवाले के रूप में हुई है। इनके खिलाफ संभाजीनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब छात्र स्कूल जा रहे थे, तभी दोनों आरोपी उनके पास पहुंचे और किसी

स्कूल संचालक के पिता बालासाहेब शिंदे पर हमला कर दिया। इस हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं। बाद में उन्हें अंबाजोगाई वे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह गुरुकुल पिछले तीन वर्षों से अर्जुन महाराज शिंदे चला रहे हैं। इस समय यहां 42 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो भजन, कीर्तन और मृदंगम जैसे विभिन्न संगीत विधाओं की शिक्षा लेते हैं। साथ ही ये छात्र किसी अन्य स्कूल में अपनी नियमित पढ़ाई भी करते हैं। निरीक्षक धनंजय ढोणे ने बताया कि मामला संभाजीनगर थाने में दर्ज किया गया है। गुरुकुल के प्रमुख अर्जुन



परीक्षा से जुड़े विवाद को लेकर उन्हें धमकाने लगे। इस बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद दोनों आरोपी स्कूल के अंदर घुस गए और वहां तोड़फोड़ की। उन्होंने स्कूल में 11 छात्रों पर बेल्ट और डंडों से हमला कर दिया। घायल छात्रों को अस्पताल ले जाने के बाद हमलावर दोबारा लौटे और

महाराज शिंदे ने हमलावरों के साथ किसी भी व्यक्तिगत विवाद से इनकार किया। उन्होंने कहा, हम तीन साल से इस गुरुकुल को चला रहे हैं और हमलावरों के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। इसके बावजूद, वे स्कूल में घुस आए और छात्रों तथा मेरे पिता पर हमला किया।

विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत सोलापुर रेलवे स्टेशन पर ‘अमृत संवाद’ का आयोजन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल के सोलापुर मंडल ने रेलवे अधिकारियों, यात्रियों और हितधारकों के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रहे विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत सोलापुर रेलवे स्टेशन पर ‘अमृत संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय रेल की नागरिक सहभागिता और निरंतर सेवा सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, अमृत संवाद पहल मंडल के विभिन्न अमृत स्टेशनों पर आयोजित की जा रही है। सोलापुर में आयोजित इस कार्यक्रम में यात्रियों, चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों को यात्री अनुभव और स्टेशन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर एक साथक संवाद के लिए एक साथ लाया गया।

पर चर्चा हुई: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए गए सुधारों का मूल्यांकन चल रहे विकासात्मक पहलों के बारे में नागरिकों से प्रतिक्रिया यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए सुधार के

बारे में जागरूकता बढ़ाना मंडल रेल प्रबंधक, सोलापुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों जैसे सीनियर डीसीएम, सीनियर डीईएन (को) सीनियर डीईई (जी) तथा एडीईएन यू ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और भविष्य में स्टेशन के सुधार के प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुमूल्य जानकारी एकत्र की।



अमृत संवाद ने रेलवे और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच एक सेतु का काम किया और पारदर्शिता, समावेशिता और नागरिक-केंद्रित पहलों के प्रति भारतीय रेल की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया। इसने यात्री सुविधाओं, बुनियादी ढाँचे और समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के प्रति सोलापुर मंडल के समर्पण को भी दर्शाया।

अन्य क्षेत्रों की पहचान भारतीय रेल की विकास यात्रा में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना स्वच्छता बनाए रखने और स्टेशन के रखरखाव में यात्रियों की भूमिका के

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई नगर निगम ने 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक शास्त्रीय मराठी भाषा दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया और नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के मार्गदर्शन में शास्त्रीय मराठी भाषा सप्ताह का बड़े उत्साह के साथ समापन किया। मराठी भाषा और साहित्य प्रेमी नागरिकों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन नगर-स्तरीय कार्यक्रमों के समान, 21 जुलाई, 2025 के सरकारी परिपत्र के अनुसार, जैसा कि नवी मुंबई नगर निगम शिक्षा विभाग की ओर से उपायुक्त श्री संघरत्न खिल्लारे द्वारा बताया गया है, शहर के सभी प्रबंधन और माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ नगर निगम के विद्यालयों में भी 3 से 9 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इनमें से कुछ विद्यालयों में

विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर अभिभावकों को भी विद्यालय में बुलाकर विभिन्न लेखकों के बारे में जानकारी दी गई, प्रख्यात लेखकों की पुस्तकें दी गईं और उन्हें मराठी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो

बात को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों को ‘लिखावट कैसे सुधारें’ और ‘अच्छी लिखावट के नियम’ पर विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क मार्गदर्शन दिया गया। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा स्वयं रचित कविताएँ सुनाने की पहल भी की गई। इस अवसर पर शिक्षकों,



विद्यार्थियों और कुछ अभिभावकों द्वारा प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का पाठ भी किया गया। विद्यार्थियों की कविताओं का एक प्रतिनिधि संग्रह भी प्रकाशित किया गया। इसी प्रकार, विद्यालय पर समूह स्तर पर कक्षावार कहानी वाचन और कविता पाठ का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों ने समूह के रूप में एक साथ कविता पाठ का आनंद लिया। कुछ विद्यालयों में, सातवीं और आठवीं कक्षाओं के लिए कहावतें और कहावत

व्याख्याकार जैसी नवीन पहल लागू की गई। मराठी भाषा के प्रसार और संरक्षण को अधिकतम करने तथा आपसी संवाद के माध्यम से मराठी भाषा को जीवित रखने के लिए, अभिभावकों की बैठक में अभिभावकों को मराठी में व्यवसाय करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। छात्रों को शुद्ध भाषा उच्चारण के बारे में भी मार्गदर्शन दिया गया और उन्हें मराठी भाषा बोलना ज़रूरी बताया गया। शास्त्रीय मराठी भाषा सप्ताह के दौरान, नवी मुंबई के स्कूलों में मराठी भाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। उल्लेखनीय है कि इसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल करके शास्त्रीय मराठी भाषा के महत्व को व्यापक रूप से बताया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि इसके विकास में सभी को अपना योगदान देना चाहिए, शिक्षा अधिकारी श्री सुलभा बरघरे ने बताया।

मनपा आयुक्त द्वारा शहरी वन पार्क का उद्घाटन पर्यावरण संरक्षण और हरित क्रांति के लिए 50 हजार वृक्षों का संकल्प

मंत्र भारत। भाईदर 11 अक्टूबर को, उत्तन स्थित ठोस अपशिष्ट परियोजना क्षेत्र में जापानी मियावाकी अवधारणा के अंतर्गत विकसित शहरी वन/पार्क का उद्घाटन मीरा भयंदर मनपा आयुक्त एवं प्रशासक, राधाबिनोद ए. शर्मा (बी.पी.एस.) के हाथों से हुआ। शहर में हरित पट्टी बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन प्राप्त करने के उद्देश्य से 50,000 पेड़ लगाने की एक व्यापक पहल को क्रियान्वित कर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना, दुर्गंध को नियंत्रित करना और शहर की सुंदरता को बढ़ाना है। साथ ही, इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों में वृक्षारोपण की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

इस क्षेत्र में हरित क्षेत्र बनाने और पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता को बढ़ाने के संदर्भ में एक आदर्श स्थापित

प्रतिनिधियों, मनपा स्कूल के छात्रों और नगर निगम कर्मचारियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प



कर रहा है। यह परियोजना केशव सुष्टि संस्था द्वारा क्रियान्वित की जा रही है और एचडीएफसी लाइफ के सीएसआर फंड के माध्यम से इस पहल को साकार किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद आयुक्त, केशव सुष्टि संस्था के प्रतिनिधियों, एचडीएफसी लाइफ के

लिया। पौधारोपण से पहले, भूमि का संतुलन बनाए रखने के लिए जगह को साफ करके 3 फीट गहराई तक खोदा गया और उस पर लाल मिट्टी की डेढ़ फीट की परत चढ़ाई गई। ऊपर से मिट्टी और गोबर का मिश्रण डालकर संतुलन बनाए

रखा गया। इसके बाद, व्यवस्थित तरीके से पेड़ों की कतारें लगाई गईं। पेड़ों को आवश्यक पोषण प्रदान करने के लिए प्रत्येक गड्ढे में नीम, कोकोपीट और वर्मीकम्पोस्ट डाला गया। साथ ही, पेड़ों की निरंतर और स्वस्थ वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पौधारोपण के बाद ट्रिप सिंचाई प्रणाली भी लगाई गई है। मीरा-भायंदर मनपा, केशव सुष्टि और एचडीएफसी लाइफ के संयुक्त प्रयासों से कार्यान्वित यह पहल प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और नागरिकों के स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक कदम है। विभिन्न स्थानीय वृक्ष प्रजातियों के रोपण से अगले कुछ वर्षों में मीरा-भायंदर नगर निगम क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ेगा, हवा स्वच्छ होगी और पर्यावरण को अधिक लचीला बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, ऐसी पहलों को सफल बनाने के लिए तीनों पीपीजी यानी सार्वजनिक, निजी और सरकारी की संयुक्त भागीदारी आवश्यक है। साथ ही, वृक्षारोपण के बाद उनका संरक्षण और संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मनपा आयुक्त ने अपने विचार रखे।

कांग्रेस ने फडणवीस की तुलना मुगलों से की, अव्यवस्था का लगाया आरोप; भाजपा ने भी किया पलटवार

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में जारी गर्माहट के बीच राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा जुबानी हमला बोला। उन्होंने फडणवीस की तुलना मुगल शासकों से कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस राज्य में अव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं और गलत काम करने वाले मंत्रियों को बचा रहे हैं। सपकाल ने कहा कि जैसे पहले मुगल थे, वैसे ही अब राज्य में फडणवीस की ‘शाही’ चल रही है। सपकाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि महायुति के मंत्रियों को खुली छूट है ‘जो करना है करो, फडणवीस आपके साथ हैं’।

इसमें गृह राज्यमंत्री योगेश कदम की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जूताकांड और किसान कर्जमाफी की मांग सपकाल कल्याण में डिट्टी पुलिस

फेंकने की कोशिश की थी। सपकाल ने इसे संविधान और न्यायपालिका का अपमान बताया। उन्होंने किसान कर्जमाफी की भी मांग दोहराई। भाजपा का पलटवार- इटली के मानसिक गुलाम



गैंगस्टर निलेश घायवाल के भाई सचिन घायवाल को कोई हथियार लाइसेंस नहीं दिया गया है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पुणे पुलिस की आपत्तियों के बावजूद सचिन को लाइसेंस दिया गया।

कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर भाजपा बैठे थे। यह प्रदर्शन उस घटना के खिलाफ था जिसमें वरिष्ठ वकील राकेश किशोर ने बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता

वहीं कांग्रेस नेता के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार कर जमकर निशाना साधा। पार्टी के मीडिया प्रमुख नवनाथ बन ने सपकाल की तुलना जलियांवाला बाग के जनरल डायर से की। उन्होंने कहा कि जनरल डायर ने गोलियां चलाई थीं, सपकाल अब जुबानी जहर फैला रहे हैं। ये लोग आज भी इटली के गुलाम हैं। इनके लिए भारत नहीं, केवल सोनिया गांधी की दरबार ही सब कुछ है। उन्होंने फडणवीस को किसानों और महाराष्ट्र की शान बताया और कहा कि जनता ऐसे नेताओं को वोट के जरिए जवाब देगी। कांग्रेस कार्यकर्ता से बदसलूकी पर भी विरोध इसके साथ ही इस दौरान पिछले महीने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मोदी की मोर्फ की गई फोटो शेयर करने पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को साड़ी पहनाकर सरेंआम बैड़जत किया। कांग्रेस ने इस मामले में एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की मांग की है।

दिवाली को लेकर क्या बोल गए NCP विधायक संग्राम जगताप? अजित पवार बोले- जारी करेंगे कारण बताओ नोटिस

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र में एनसीपी गुट के विधायक संग्राम जगताप के दिवाली की खरीदारी को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। आरोप-प्रत्यारोप की बीच अब पार्टी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। इसके तहत उन्होंने

मामले में संज्ञान लेते हुए पार्टी के विधायक संग्राम जगताप को उनके कथित विवादित बयान के लिए कारण बताओ नोटिस (शो-काँज नोटिस) भेजने की बात कही है। पवार ने शनिवार को कहा कि पार्टी विधायक संग्राम जगताप को उनके बयान के लिए कारण बताओ नोटिस (शो-काँज नोटिस) भेजा जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार उन मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिनमें जगताप पर लोगों से दिवाली पर



केवल हिंदू दुकानदारों और व्यापारियों से खरीदारी करने की अपील करने का आरोप लगाया गया था। जगताप पर यह आरोप है कि उन्होंने लोगों से दिवाली की खरीदारी सिर्फ हिंदू दुकानदारों से करने की अपील की थी। मीडिया में आई इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए अजित पवार ने कहा कि यह बयान पूरी तरह से गलत है। जब पार्टी की नीतियां और उद्देश्य पहले से तय हैं, तो किसी विधायक को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पार्टी



सम्पादकीय

हरियाणा शिक्षक स्थानांतरण: नीति, प्रक्रिया और भ्रम

(वित्त विभाग की स्वीकृति, स्थानांतरण में देरी, दंपति मामले, मध्यावधि स्थानांतरण, ऑनलाइन व्यवस्था, नई नियुक्तियाँ, प्रतिनिधिमंडल और निष्पक्षता के बहाने।)

वित्त विभाग से अतिरिक्त भत्तों की स्वीकृति के बावजूद, फाइलों का बार-बार लंबित रहना कर्मचारियों में भ्रम पैदा करता है। वैवाहिक मामलों में पहले से चल रहे मामलों के बावजूद प्रक्रिया को फिर से शुरू करना इस बात का संकेत है कि नीति को जानबूझकर जटिल बनाया गया है ताकि निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मध्यावधि स्थानांतरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। इन सभी कारणों से शिक्षक असंतुष्ट हैं और शिक्षा की गुणवत्ता और संतुलन बनाए रखने के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को स्पष्ट, समयबद्ध और निष्पक्ष बनाना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि मध्यावधि स्थानांतरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वास्तव में, प्रशासन अक्सर इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करता है। केवल एक पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष प्रक्रिया ही शिक्षकों और छात्रों के हित में स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकती है।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा में शिक्षकों के स्थानांतरण और नियुक्ति की प्रक्रिया वर्षों से विवाद और असंतोष का विषय रही है। शिक्षकों और कर्मचारियों का मानना ​​​​? है कि नीतियाँ, अपनी घोषणाओं में स्पष्ट होते हुए भी, वास्तव में जटिल और पेचीदा हैं। यह मुद्दा केवल कर्मचारियों के हितों का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, निष्पक्षता और गुणवत्ता का भी है।

वित्त विभाग द्वारा किसी पद को स्वीकृत किए जाने के बाद भी, स्थानांतरण प्रक्रिया में अक्सर अनावश्यक देरी हो जाती है। ऐसा बाजरी बाधाओं, दस्तावेज़ीकरण या प्रशासनिक स्तर पर बार-बार अनुमोदन की अनावश्यक आवश्यकता के कारण होता है। यह देरी न केवल प्रक्रिया को धीमा करती है, बल्कि नीति के उचित और समय पर कार्यान्वयन में भी बाधा डालती है। कर्मचारी महीनों तक अनिश्चितता में रहते हैं, जिससे उनका मनोबल गिरता है और शिक्षा प्रणाली की दक्षता प्रभावित होती है।

विवाहित मामलों में, जहाँ शिक्षक अपने जीवनसाथी के साथ पदस्थापन चाहते हैं, पहले से लंबित मामलों के बावजूद पुनर्परीक्षण और अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इससे कर्मचारियों को अनावश्यक असुविधा होती है और नीति की जटिलता उजागर होती है। यह इस बात का भी संकेत है कि प्रशासन कभी-कभी जानबूझकर प्रक्रिया को लंबा खींचता है।

थानांतरण को रोकने में कई कारक शामिल होते हैं। दीर्घकालिक कर्मचारी अपने पद छोड़ने से हिचकिचाते हैं। यूनियन और संगठन अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करते हैं। इसके अलावा, प्रशासन अनुभवी कर्मचारियों को संवेदनशील पदों पर लंबे समय तक बनाए रखना पसंद करता है। इन सभी कारणों से, स्थानांतरण प्रक्रिया अक्सर संतुलित और निष्पक्ष नहीं होती।

शिक्षा मंत्री ने प्रेस में कहा था कि मध्यावधि स्थानांतरण लागू किए जाएँगे, लेकिन वास्तव में, इसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं दिखता। यह विरोधाभास कर्मचारियों में भ्रम और असंतोष पैदा करता है। घोषणाओं और वास्तविक कार्यान्वयन के बीच यह अंतर यह संदेश देता है कि केवल बयानों से नीति कार्यान्वयन नहीं होता।

जबकि अन्य विभागों में ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली सुचारु रूप से लागू हो रही है, शिक्षा विभाग में यह प्रक्रिया धीमी और जटिल बनी हुई है। यह केवल तकनीकी कठिनाइयों के कारण नहीं है। प्रशासनिक प्रतिरोध, पारंपरिक कार्य संस्कृतियों और स्थानीय अधिकारियों की प्राथमिकताएँ, ये सभी इसमें योगदान करती हैं। जब तक सभी पक्ष पारदर्शिता और समय पर कार्यवाई सुनिश्चित नहीं करते, ऑनलाइन प्रणाली प्रभावी नहीं हो सकती।

नई नियुक्तियों के समय पर्याप्त पद उपलब्ध होने के बावजूद, स्थानांतरण में देरी हो रही है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या कर्मचारियों को जानबूझकर हटाया जा रहा है या कुछ को विशेषाधिकार दिया जा रहा है। आगामी वर्ष में जनगणना के कारण स्थानांतरण न होने की संभावना इस मुद्दे को और जटिल बना देती है।

प्रतिनिधिमंडल की प्रथा भी एक समस्या बनी हुई है। इसमें कर्मचारियों को विशिष्ट पदों या स्थानों पर नियुक्त करना शामिल है। यह न केवल पारदर्शिता और निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि पक्षपात और प्रशासनिक भेदभाव को भी बढ़ावा देता है। यदि इसे रोका जाए और समय पर सुधारात्मक कार्यवाई की जाए, तो शिक्षकों और विभाग दोनों को लाभ होगा।

इन सभी जटिलताओं के बावजूद, शिक्षक समुदाय चाहता है कि नीति स्पष्ट, समयबद्ध और निष्पक्ष हो। केवल घोषणाओं और प्रेस विज्ञप्तियों से समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रशासन को ऑनलाइन प्रणाली को प्रभावी बनाना होगा और पक्षपात और व्यक्तिगत लाभ पर आधारित निर्णयों को रोकना होगा। शिक्षकों और छात्रों को यह विश्वास होना चाहिए कि स्थानांतरण प्रक्रिया शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और संतुलन बनाए रखने के लिए है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए।

हरियाणा की शिक्षक स्थानांतरण नीति न केवल जटिल और पेचीदा है, बल्कि इसका कार्यान्वयन भी असंगत और निष्पक्ष है। प्रशासनिक देरी, अनावश्यक अनुमोदन, पक्षपात और तकनीकी बाधाओं के कारण शिक्षकों में असंतोष है। इससे शिक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार को स्पष्ट नियमों और नीतियों को लागू करना चाहिए, समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना चाहिए, ऑनलाइन प्रणाली को प्रभावी बनाना चाहिए,

देश-दुनिया की निगाहे माइनिंग सेक्टर तो एग्रेसिव मोड पर राजस्थान

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट से एक बात साफ हो जानी चाहिए कि आज अमेरिका ही नहीं दुनिया के अन्य देशों के लिए भी प्रधान के गर्भ में समाई खनिज संपदा महत्वपूर्ण हो गई है। अमेरिका चाहे यूक्रेन पर दबाव बना रहा हो या कनाडा को राज्य के रूप में घोषित कर अमेरिका में मिलाने की छटपटाहट हो या अन्य देशों की और भ्रुकुटी तानने या मेल मिलाप के प्रयास हो सब कुछ इस खनिज संपदा को लेकर ही है। आजा चाइना की मोनोपोली देखने को मिल रही है उसका बड़ा कारण भी उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट सहित आज के बदलते युग की मांग को पूरी करने वाली पुरासंपदा के अथाह भण्डार के कारण ही है। ऐसे में वैसे तो दुनिया के देश खनि संपदा को लेकर गंभीर है वहीं हमारे देश में भी केन्द्र और राज्य सरकारें खनिज खोज, खनन और खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की कमर कस ली है। ऐसे में राजस्थान सरकार भी माइनिंग सेक्टर प्रोएक्टिव भूमिका निभाते हुए आगे आया है। वर्तमान सरकार खासतौर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को खनन क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। राजस्थान की सरकार द्वारा योजनाबद्ध प्रयासों के तहत प्रदेश में खनिज से जुड़े सभी पहलुओं के योजनाबद्ध क्रियान्वयन, समन्वय, प्रबंधन, प्रभावी मोनेटरिंग, एक्सप्लोरेशन, राजस्व, निवेश एवं रोजगार बढ़ोतरी, सस्टेनेबल माइनिंग, माइनिंग सेक्टर में देश दुनिया में हो रहे नवाचार और नवीतम तकनीक और उसके प्रदेश में उपयोग सहित



जाएगा। इससे खानें जल्दी परिचालन आने के साथ ही निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वैसे भी आने वाले समय में माइनिंग सेक्टर की भूमिका में बड़ा बदलाव आने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रप्रति ट्रंप की छटपटाहट से इसे आसानी से समझा जा सकता है। अमेरिका कभी कनाडा को अमेरिका का राज्य ही बनाने में जुटा है तो यूक्रेन की खनिज संपदा अपने नाम करवाने या रूस पर दबाव बनाने के पीछे धरती के गर्भ में समाई खनिज संपदा ही है। खनिज संपदा पर आज दुनिया के देशों की नजर है। चीन के वर्चस्व का बड़ा कारण उसका आरईई सहित खनिज संपदा पर एकाधिकार ही है और आज चीन के इस वर्चस्व को कम करने में ही

जुटे हुए हैं। खैर यह विषयांतर होगा पर एक बात साफ है कि माइनिंग सेक्टर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व व मार्गदर्शन में तेजी से काम होने लगा है और राजस्थान ऑक्शन सहित रेवेन्यू अर्जन विकास दर आदि में अब्वल हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा माइनिंग सेक्टर में विपुल संभावनाओं

को देखते हुए राजस्थान के माइनिंग सेक्टर को देश में अग्रणी राज्य बनाने पर जोर देते रहे हैं। नई खनिज नीति, एम-सेण्ड नीति, रिस्स में सहायता प्रावधान, एमनेस्टी योजना सहित प्रक्रिया के सरलीकरण और खनन क्षेत्र विकास के महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। पीएमयू के गठन के साथ ही खनन क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों को 7 सेक्टरों में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सचिव माइन्स टी रविकान्त का मानना है कि सभी क्षेत्रों में समन्वित व तेजी से विकास के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ते हुए पीएमयू का गठन किया गया है जिससे योजनाबद्ध तरीके से तेजी से आगे बढ़ा जा सके। एक्सप्लोरेशन, ऑक्शन, शीथ

परिचालन, रिसर्च एवं डेवलपमेंट, जीरो लॉस माइनिंग, इकोटूरिज्म की संभावनाओं, पेपरलेस सहित विभिन्न गतिविधियों का समावेश किया गया है। विभाग के वरिष्ठ व विशेषज्ञ अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। खनिज क्षेत्र से जुड़े 7 प्रमुख सेक्टरों में से पहले एक्सप्लोरेशन व ऑक्शन का बनाया गया है। इस दल द्वारा कोमोडिटी, मिनरल ग्रेड, खनन के प्रकार सहित विभिन्न बिन्दुओं पर कार्य करेगी। यह दल जीएसआई सहित तकनीकी विशेषज्ञों से समन्वय बनाते हुए एक्सप्लोरेशन से ऑक्शन आदि संबंधित कार्यों को और अधिक प्रभावी गति दी जा सकेगी। इसी तरह से ऑक्शन किये गये माइनर और मिनरल ब्लॉकों को जल्द से जल्द परिचालन में लाने के लिए संबंधित स्ट्रेक होल्डर्स व खान विभाग सहित संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए आवश्यक अनुमतियाँ दिलाने में सहयोग के साथ ही शीघ्र परिचालन में लाने का कार्य करेगी। विभाग का जोर खनन क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने और राजस्व में किसी भी तरह की छीजत को रोकना भी है और इसके लिए एक दल को मोनेटरिंग सहित आवश्यक सभी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। डीएमएफटी के कार्य को गति देने और राशि के बेहतर उपयोग की मोनेटरिंग की जिम्मेदारी सौंपते हुए डीएमएफटी फण्ड के अन्य प्रदेशों में उपयोग को लेकर अध्ययन सहित योजना, क्रियान्वयन व मोनेटरिंग का फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा गया है। राज्य सरकार का सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर रहने के साथ ही बदलते परिवेश में यह आवश्यक भी हो गया है। सस्टेनेबल माइनिंग और ऑटोमेशन और तकनीक सेक्टर दल द्वारा स्टार रेटिंग,

बंद व कार्य नहीं कर रही खानों में इको टूरिज्म की संभावनाओं व क्रियान्वयन, डम्प ओवरबर्डन आदि के रिसाइक्लिंग व उपयोग, श्रेष्ठ कार्य करने वाली खानों को प्रोत्साहित करने के साथ ही विभागीय सिस्टम को नई तकनीक से जोड़ने और पेपरलेस करने की दिशा में कार्य दिया गया है। इसी तरह से खनिज क्षेत्र में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने, अधिकारियों के रिओरियंटेशन, खनन क्षेत्र से जुड़े स्ट्रेक होल्डर्स व विभाग के बीच साझा मंच उपलब्ध कराने, देश दुनिया में तकनीक में आ रही बदलाव से रुबरु कराने सहित इस तरह के कार्यों के लिए कॉन्क्लेव, सेमिनार, संगोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा व आयोजन का काम किया जाएगा। राज्य सरकार ने पीएमयू गठित कर जिम्मेदारी तय करने के साथ ही सरकार की ईच्छा शक्ति स्पष्ट कर दी है। अब पीएमयू टीम को जी जान से जुटते हुए माइनिंग के सभी क्षेत्रों में करेगी। विभाग का जोर खनन क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने और राजस्व में किसी भी तरह की छीजत को रोकना भी है और इसके लिए एक दल को मोनेटरिंग सहित आवश्यक सभी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। डीएमएफटी के कार्य को गति देने और राशि के बेहतर उपयोग की मोनेटरिंग की जिम्मेदारी सौंपते हुए डीएमएफटी फण्ड के अन्य प्रदेशों में उपयोग को लेकर अध्ययन सहित योजना, क्रियान्वयन व मोनेटरिंग का फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा गया है। राज्य सरकार का सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर रहने के साथ ही बदलते परिवेश में यह आवश्यक भी हो गया है। सस्टेनेबल माइनिंग और ऑटोमेशन और तकनीक सेक्टर दल द्वारा स्टार रेटिंग,

बसपा ने फिर दिखाई ताकत, मायावती के सियासी दांव से सपा को 'तनाव'

मृत्युंजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से लेकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों तक की चहल-पहल दिखने लगी है। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो बहिन मायावती ने मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए कई राजनैतिक संदेश दिए। बहिन मायावती ने अपनी जनसभा में एक ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करके राजनैतिक विश्लेषकों को हैरान किया तो दूसरी ओर अगले विधानसभा चुनावों में बिना किसी गठबंधन के उतरने की घोषणा भी कर दी है। बसपा के शक्ति प्रदर्शन को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बसपा की बढ़ती ताकत से समाजवादी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। बहिन मायावती ने न केवल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की अपितु यह भी कहा कि यदि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी जुमला न सबित हुआ तो वह पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होगी। बहिन मायावती अपनी 2007 की रणनीति को अपनाते हुए पुनः सामाजिक न्याय को आधार बनाकर ही चुनावी मैदान में उतरेंगी ऐसा संकेत उनकी रैली से मिलता है। उन्होंने अपनी रैली में भीड़ जुटा कर यह संदेश दे दिया है कि उनका कोर वोटबैंक जाटव व दलित अभी भी उनके साथ है, भले ही इस

समय उनके पास विधानसभा में केवल एक विधायक और मात्र 9 प्रतिशत वोट हैं। बहिन मायावती अपनी रैली में भाजपा के प्रति नरम व सपा तथा कांग्रेस के प्रति गरम दिखाई पड़ीं। उन्होंने अपनी रैली में कांग्रेस व सपा पर जमकर हमला



बोलते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान पर नाटकबाजी कर रही है। कांग्रेस ने देश पर आपातकाल लगाकर बाबा साहब के बनाए संविधान का अपमान किया था। कांग्रेस ने बाबा साहब का कभी भी सम्मान नहीं किया। उन्होंने केंद्र सरकार में रहने पर उन्हें आयकर और सीबीआई की जांच में फंसाने की कोशिश की ताकि डा. आंबेडकर और कांशीराम

को कारवां को रोका जा सके। अब उसी कांग्रेस के लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर नाटकबाजी कर रहे हैं। सपा के प्रति नरम व सपा तथा कांग्रेस के प्रति गरम दिखाई पड़ीं। उन्होंने अपनी रैली में कांग्रेस व सपा पर जमकर हमला

को कांग्रेस के लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर नाटकबाजी कर रहे हैं। सपा के प्रति नरम व सपा तथा कांग्रेस के प्रति गरम दिखाई पड़ीं। उन्होंने अपनी रैली में कांग्रेस व सपा पर जमकर हमला

को कांग्रेस के लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर नाटकबाजी कर रहे हैं। सपा के प्रति नरम व सपा तथा कांग्रेस के प्रति गरम दिखाई पड़ीं। उन्होंने अपनी रैली में कांग्रेस व सपा पर जमकर हमला

को कांग्रेस के लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर नाटकबाजी कर रहे हैं। सपा के प्रति नरम व सपा तथा कांग्रेस के प्रति गरम दिखाई पड़ीं। उन्होंने अपनी रैली में कांग्रेस व सपा पर जमकर हमला

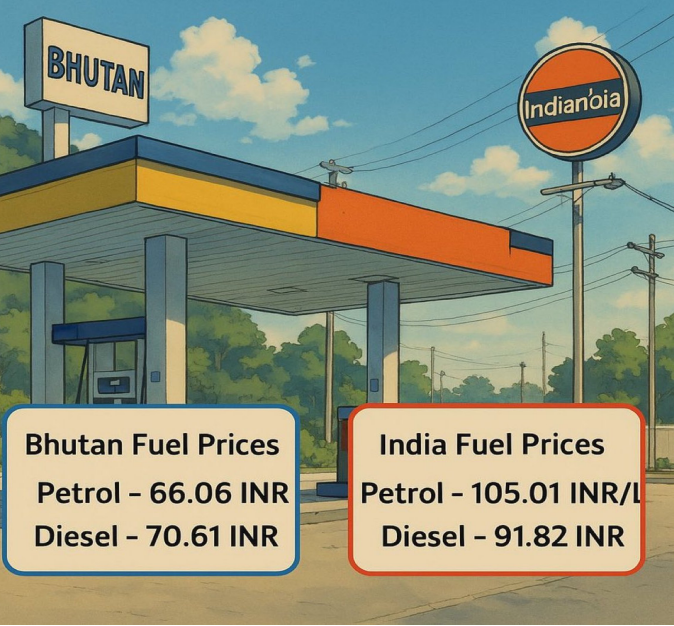
पेट्रोल पुराण : या इलाही ये माजरा क्या है ?

निर्मल रानी

विश्व के अधिकांश देशों में पेट्रोल डीज़ल की कीमतें भिन्न भिन्न हैं। प्रत्येक देशों में ईंधन रुपी इन तेलों की कीमतों का निर्धारण वहां के टैक्स दर, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय, कीमत, करोंसी एक्सचेंज रेट, रिफ़ाइनिंग लागत, स्थानीय मांग और सरकारी नीतियों के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त अधिक आयात शुल्क, वैट, और स्थानीय कर भी ईंधन की कीमत के निर्धारण के मुख्य कारक होते हैं। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहाँ देश की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने जैसे सड़क निर्माण, इनके रखरखाव व अन्य विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिए ईंधन पर भारी टैक्स लगाया जाता है। तेल की कीमतों के निर्धारण में तेल उत्पादक देशों से कच्चा तेल आयात करने का खर्च भी एक खास वजह होती है। कच्चा तेल आयात करने वाले देशों को वृद्धि डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में यदि किसी देश की अपनी मुद्रा, डॉलर के मुकाबले कमजोर है अथवा कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ जाते हैं, तो ईंधन स्वभाविक रूप से महंगा हो जाता है। इसके अलावा अलग-अलग ग्रेड के स्वच्छ ईंधन बनाने के लिए वाली रिफ़ाइनिंग और वितरण की लागत भी तेल की कीमत में जुड़ जाती है। मांग और आपूर्ति भी तेल कीमतों के निर्धारण का बड़ा कारक



₹64.38 प्रति लीटर है जबकि डीज़ल का मूल्य लगभग 64.27 प्रति लीटर है। भूटान में ईंधन की कीमतों में कमी का सबसे मुख्य कारण यही है कि भूटान सरकार इन पर बहुत ही कम टैक्स लगाती है। दूसरी बात यह भी कि भारत में पेट्रोल में 20₹ इथेनॉल (गन्ने के रस से प्राप्त होने वाला रसायन) मिलाता अब अनिवार्य हो गया है गोया भारत में 20 इंधन मिलता है। परन्तु भूटान में बिना इथेनॉल के पेट्रोल उपलब्ध है। यानी भूटान में भारत की तुलना में पेट्रोल शुद्ध भी है और कीमतें भी अलग



हैं। यही वजह है कि सीमावर्ती भारतीय अपने वाहनों में तेल डलवाने भूटान चले जाते हैं। अब रहा सवाल पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का तो दुनिया के कई देशों में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है। ऐसा करने का मकसद पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के साथ ही तेल की खपत कम करना बताया जा रहा है। ब्राज़ील, अमेरिका, भारत, और अनेक यूरोपीय देश ऐसे हैं जहाँ पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है। भारत सरकार ने तो पेट्रोल में 20₹ इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले ही

पूरा कर लिया है और आज यही 20 इंधन देश के सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्ध है। अधिकतर पेट्रोल पंप पर इस बात की सार्वजनिक सूचना नहीं होती कि उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। इस जानकारी के अभाव में उपभोक्ता अपने वाहन में 20 इंधन व भरवा लेते हैं और यही लोग बाद में भ्रम पर संभावित दुष्प्रभाव को भी झेलते हैं। पर्यावरण दुष्प्रभाव व तेल की खपत कम करने की गरज से भले ही भारत सहित दुनिया के अनेक देश पेट्रोल में इथेनॉल क्यों न मिला रहे हों परन्तु

दी जाती है। इन हालात में भारतीय ईंधन उपभोक्ताओं का यह सवाल पूरी तरह जायज़ है कि आखिर सरकार की यह कैसी नीति है जिसके तहत भारत से निर्यातित पेट्रोल डीज़ल पड़ोसी देश भूटान में तो अत्यधिक सस्ता यानी लगभग 64 रुपये प्रति लीटर के दर पर उपलब्ध है जबकि वही तेल निर्यातित देश भारत के लोगों को 103 रुपये से लेकर 105 रुपये प्रति लीटर तक बेचा जा रहा है? साथ ही भूटान में तो भारत 100 ₹ शुद्ध तेल भेजता है जबकि भारत में 20₹ इथेनॉल मिश्रित कर तेल बेचा जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश भूटान की सरकार को अपने देश के पर्यावरण की फ़िक्र नहीं ? और एक सवाल यह भी कि अनेक प्रकार के करों से राहत देकर जिस तरह भूटान की सरकार भूटान वासियों को तेल की कीमत में राहत दे रही है भारत सरकार भी ऐसा क्यों नहीं करती ? भारत के इस निराले 'पेट्रोल पुराण' को लेकर यह सवाल भी जरूरी है कि क्या देश के वाहनों में ईंधन में 20₹ इथेनॉल मिश्रण के चलते आने वाली वित्तीय व इंजन संबंधी खर्चाियों की फ़िक्र सरकार को नहीं ? या फिर महंगा तेल और मिलावटी तेल का मकसद तेल कंपनियों, तेल व्यवसायियों को लाभ पहुँचाने के साथ साथ वाहन निर्माता कंपनियों को भी फ़ायदा पहुँचाना और भारतीय वाहन धारकों को जेबें ढीली करना है ? इसीलिये आज पूरा देश इस 'पेट्रोल पुराण' पर यह सवाल पूछ रहा है कि या इलाही ये माजरा क्या है ?



भिवंडी मनपा प्रभाग समिति तीन कार्यालय के सामने कचरे का अंबार,बदबू से फैल रही बीमारी ठेकेदार व कर्मचारियों की उदासीनता पर भड़के समाजसेवक,इस्तीफे की किया मांग

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी मनपा के प्रभाग समिति तीन कार्यालय के सामने से रोजाना कचरा न उठाए जाने के कारण इन दिनों कचरे का अंबार लगा हुआ है।जिसके कारण उठाने वाले दुर्गंध व बदबू के कारण लोगों का न सिर्फ जीना दुश्धार कर दिया है।बल्कि स्थानीय लोग इस कारण तरफ तरफ की बीमारी की चपेट में फंस रहे हैं।जिसे लेकर लोगों में प्रशासन के प्रति घोर आक्रोश व्याप्त है।

स्थानीय निवासी व समाजसेवक रितेश जाधव ने बताया कि मनपा के प्रभाग समिति तीन कार्यालय के गेट के बगल में इन दिनों कचरे का ढेर लगा हुआ है।उन्होंने बताया कि रोजाना कचरा न उठाए जाने के कारण



भिवंडी मनपा स्कूल, कोंबरपाड़ा में पानी शुद्धिकरण संयंत्र और पानी ठंडा करने की मशीन का उद्घाटन

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी मंगेश यादव और विनोद येनागंदला द्वारा, एस आर ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के चेयरमैन रमाकांत पांडा द्वारा पूर्व नगरसेवक एड हर्षल पाटिल के प्रयत्न से भिवंडी मनपा स्कूल नंबर 28, कोंबरपाड़ा में पानी शुद्धिकरण संयंत्र और पानी ठंडा करने की मशीन जकल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दान दी गई। जिसका उद्घाटन रमाकांत पांडा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में शिवम झा, कृष्णा गाजेंगी, राजू गाजेंगी, भावेश पाटिल के साथ ट्रस्ट के सदस्य मनीष यादव, समीर शेख, सुभाष पासवान, मुकेश चौबे, अजय यादव, मुकेश झा, मंजुलता दुबे, पुनम कनोजिया, स्कूल के शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित थे।इसके पहले उक्त



संस्था ने धामनकर नाका इलाके में स्थित सत्यनारायण हिंदी हाई स्कूल में पानी शुद्धिकरण संयंत्र और पानी ठंडा करने की मशीन लगाकर दिया

था।जिससे बच्चे को शुद्ध व साफ पानी पीने के लिए मिल रहा है।ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना हो रही है।

इस कारण इलाके में दमघोंटू बदबू उठ रही है। इसकी वजह से पैदा होने वाले मच्छरों के कारण इलाके के लोग डेंगू जैसे बीमारी के चपेट में फंस रहे हैं।साथ ही दूसरे इलाके में रहने वाले व प्रभाग कार्यालय में टैक्स आदि भरने के लिए आने वाले लोगों को भी कचरे के ढेर से मुंह बंद कर गुजरना पड़ता है।जबकि सफाई ठेकेदार व मनपा स्वच्छता विभाग के कर्मचारियों के अनदेखी व अकर्मण्यता के कारण पूरे 16 नंबर वार्ड कचरे से पटा पड़ा है।रितेश जाधव ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस वार्ड में कई दिनों तक कचरा नहीं उठाया जाता है।जिसके कारण लोग तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं।वार्ड में दवा का छिड़काव व धुंआ न मारे जाने के कारण पूरे वार्ड में मच्छरों का आतंक बढ़ाते जा रहा है।उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब ठेकेदार व मनपा कर्म अपने कार्यालय के सामने से

रोजाना कचरा नहीं उठा सकते हैं तो उनसे वार्ड की सफाई की क्या उम्मीद किया जाय? समाजसेवक रितेश जाधव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मनपाकर्मियों से काम नहीं हो सकता तो सभी को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए।साथ ही उन्होंने मनपा आयुक्त अनमोल सागर व स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त विक्रम दराडे से सफाई निरीक्षक को निलंबित कर सफाई ठेकेदार का ठेका, काम में लापरवाही बरतने के कारण रह कर उसे ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है।हालांकि इस मामले में प्रभाग समिति दो के सहायक आयुक्त सुरेन्द्र भोईर से तथा उपायुक्त से इस संदर्भ में बात करने की कोशिश की गई ,लेकिन उन्होंने शनिवार का दिन होने के कारण कॉल उठाकर कुछ भी जवाब देने की जहमत नहीं उठाया।सफाई के अभाव में 16 नंबर वार्ड में प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ते जा रहा है।

भिवंडी में पूर्व भाजपा नेता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

भिवंडी। संवाददाता भिवंडी भाजपा शहर ज़िले के पूर्व सचिव बालमुकुंद शुक्ला को चेक बाउंस के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें 15 हजार रुपये के मुचलके और एक जमानतदार



की गारंटी पर रिहा कर दिया। साथ ही, अदालत ने आरोपी को हर सुनवाई पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता पत्रकार फहीम अंसारी वेड अनुसार, एक आर्थिक लेनदेन के तहत बालमुकुंद शुक्ला ने उन्हें अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का चार लाख रुपये का चेक दिया था। जब यह चेक बैंक में जमा किया गया, तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद जब अंसारी ने शुक्ला से भुगतान की मांग की, तो उन्होंने

भाजपा का नेता होने का रोब दिखाते हुए धमकी दी और पैसे लौटाने से इंकार कर दिया। अंसारी ने 9 सितंबर 2024 को भिवंडी अदालत में धारा 138 (चेक रिटर्न अधिनियम) के तहत मामला दर्ज कराया। इसके बाद बालमुकुंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए शांतीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करावाई कि उनका चेक चोरी हो गया है। अदालत की सुनवाई के दौरान शुक्ला कई बार गैरहाज़िर रहे, जिसके चलते अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (N) जारी किया। इसी वारंट के तहत 9 अक्टूबर 2025 की शाम भिवंडी शहर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर

10 अक्टूबर को अदालत में पेश किया।बालमुकुंद मिश्रा से मोबाइल द्वारा संपर्क करने पर उन्होंने बताया चेक चोरी के मामले की जांच जारी है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा की मुख्य बाड़ी बर्खास्त हो चुकी है। अभी तक केवल शहर का अध्यक्ष चुना गया है।

स्वाभिमान श्री अंतर-विद्यालय वक्तृत्व प्रतियोगिता संपन्न विद्यार्थियों ने मराठी भाषाप्रति जताया अभिमान

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

अभिजात मराठी भाषा सप्ताह के उपलक्ष्य में स्वाभिमान सेवा संस्था की ओर से आयोजित 'स्वाभिमान श्री अंतर-विद्यालय वक्तृत्व प्रतियोगिता' उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। यह प्रतियोगिता संस्था के संस्थापक संतोष शेड्डी के जन्मदिन की पूर्वसंध्या पर पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालय के स्व. पुष्पलता जाधव सभागृह में आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भिवंडी महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके के हस्ते दीपप्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर संस्थापक संतोष शेड्डी, अध्यक्ष हसमुख पटेल, विद्यालय के प्राचार्य सुधीर घागस, बी.एन.एन. महाविद्यालय के उपप्राचार्य डी.एल. अहिरे, पालिका जनसंपर्क अधिकारी श्रीकांत परदेशी और सहायक आयुक्त सुरेंद्र गुलवी उपस्थित रहे।

उद्घाटन प्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त डाके ने कहा कि मराठी भाषा हजारों वर्षों की परंपरा और समृद्ध साहित्यिक

है। अटकते हुए भी मराठी बोलने में गर्व महसूस होता है, और संस्था मराठी भाषा के प्रचार-प्रसार में सदैव योगदान



वारसा समेटे हुए है। इसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक प्रयोग में लाना समय की मांग है। वहीं, संतोष शेड्डी ने कहा, 'भले ही मराठी मेरी मातृभाषा नहीं, पर महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि

देती रहेगी।'स्पर्धा दो गटों में आयोजित की गई – अ गट (कक्षा 5 से 8) तथा ब गट (कक्षा 9 से 12)। इसमें विभिन्न विद्यालयों के 38 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 'मराठी माझी

मायबोली', 'मराठी संस्कृतीचा सुवास' और 'संत साहित्याची परंपरा' जैसे विषयों पर विद्यार्थियों ने ओघवती शैली में अपने विचार प्रस्तुत किए। पुरस्कार विजेता: अ गट में पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालय की कस्तुरी श्रीनाथ भंडारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, एन.ई.एस. स्कूल के आरुध्य करले द्वितीय तथा मनहा जमीर शेख तृतीय स्थान पर रही। ब गट में बी.एन.एन. महाविद्यालय की कार्तिकी ज्ञानेश्वर पाटील ने प्रथम, आकांक्षा संककाळ ने द्वितीय और प्रतीक्षा गायकवाड ने तृतीय स्थान हासिल किया। विजेताओं को संस्थापक संतोष शेड्डी और अध्यक्ष हसमुख पटेल के हाथों नकद पुरस्कार, प्रमाणपत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। प्रतियोगिता की सफलता में संयोजक सुधीर घागस, डी.एल. अहिरे, मानसी राजे और अभिजित म्हसकर का विशेष योगदान रहा।

भदोही-मिर्जापुर और वाराणसी देश के प्रमुख कारपेट क्लस्टर : योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 49वें इंडिया कारपेट एक्सपो का किया शुभारंभ

भदोही, 11 अक्टूबर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार कालीन नगरी भदोही में 49वें इंडिया कारपेट एक्सपो का उद्घाटन फौता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी देश के प्रमुख कारपेट क्लस्टर हैं। जिन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को वैश्विक पहचान दिलाई है।

कालीन उद्योग लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रोत्साहित करने के लिए 'इंडिया एक्सपो मार्ट' की स्थापना कराई। इसका उद्देश्य था कि यहां के बुनकरों को विश्व बाजार से सीधा जोड़ने का अवसर मिले।

चार दिवसीय यह आयोजन 11 से 14 अक्टूबर तक कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एफ़्पे) के तत्वावधान में इंडिया एक्सपो मार्ट परिसर में शुरू हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बुनकरों और उद्यमियों से संवाद किया। उनकी समस्याएँ जानीं और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से उन्हें अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे इस आयोजन ने हैंडमेड कालीनों के वैश्विक व्यापार में उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। अब विदेशी खरीदार सीधे भदोही आते हैं, यहीं के बुनकरों से संवाद करते हैं

और यहीं से निर्यात के अनुबंध संपन्न होते हैं यह भदोही के गौरव की बात है।

पारंपरिक शिल्पकार या बुनकर कार्य कर रहे हैं, सरकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा, प्रशिक्षण, डिज़ाइन और ब्रांडिंग



मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार परंपरागत उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वर्ष 2018 में शुरू हुई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट (एडव्ड) योजना इसी दिशा का बड़ा कदम थी। उन्होंने बताया कि भदोही के कालीन उद्योग को एडव्ड योजना में शामिल कर विशेष सुविधाएं दी गईं। उन्होंने कहा कि 'प्रदेश में जो भी

में सहयोग दे रही है। हर पंजीकृत बुनकर को 5 लाख रुपये की सुरक्षा गारंटी दी गई है,' उन्होंने बताया कि सरकार लगातार तकनीक और बाजार की माँग के अनुसार डिज़ाइन नवाचार पर बल दे रही है ताकि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़े। मुख्यमंत्री योगी ने केंद्र सरकार के

हालिया जीएसटी सुधारों को व्यापार और उद्योग जगत के लिए ऐतिहासिक बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार के इंडिया कारपेट एक्सपो में 88 देशों से 300 से अधिक विदेशी खरीदार शामिल हुए हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है। आज जो दृश्य भदोही में है, वह दस वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। 'विदेशी खरीदार अब सीधे भदोही आकर स्थानीय बुनकरों से

किया है। मुख्यमंत्री ने भदोही के शैक्षणिक विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काशी नरेश कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। इससे क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ-साथ रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण भी मिलेगा। यह विश्वविद्यालय कारपेट क्लस्टर को कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि भदोही न केवल कालीन उद्योग का केंद्र बने, बल्कि कौशल और तकनीकी नवाचार का भी हब बने। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भदोही की कालीन केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह उद्योग सदियों पुरानी विरासत का संवाहक है। यहां के बुनकरों की मेहनत, कौशल और कला ही भदोही की पहचान है। एक्सपो जैसे आयोजन इस विरासत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिला रहे हैं। भदोही की कालीन भारत की सांस्कृतिक पहचान मुख्यमंत्री ने सभी विदेशी प्रतिनिधियों, बुनकरों और आयोजकों का स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर सशक्त बनाएगा।

गायक कुमार सानू ने व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

नई दिल्ली।जानेमाने गायक कुमार सानू ने अपने नाम, आवाज, गायन शैली और तकनीक आदि सहित अपने व्यक्तित्व और प्रसिद्धि से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। न्यायमूर्ति मनमोहन प्रीतम सिंह अरोड़ा 13 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं। सानू ने अपनी याचिका में, अपने व्यक्तित्व और प्रसिद्धि से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा का अनुरोध किया है, जिसमें उनका नाम, आवाज, गायन शैली और तकनीक और प्रस्तुतिकरण, गायन का तरीका, चित्र, कैरिकेचर, तस्वीर, समानता और हस्ताक्षर शामिल हैं। उन्होंने तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत/बिना लाइसेंस के उपयोग और/या वाणिज्यिक उपयोग के खिलाफ भी सुरक्षा का अनुरोध किया, जिससे जनता के बीच भ्रम या धोखा होने की आशंका है। अधिवक्ता शिखा सचदेवा और सना रईस

खान के माध्यम से दायर यह वाद कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों के तहत सानू को उनके प्रदर्शन में प्रदत्त नैतिक अधिकारों के उल्लंघन से भी संबंधित है। याचिका में दावा किया गया है कि प्रतिवादी सानू का नाम, आवाज, समानता और व्यक्तित्व निकालकर उनके व्यक्तित्व और प्रसिद्धि अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। याचिका में दावा किया गया है कि गायक को विभिन्न जीआईएफ, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से भी पीड़ा हुई है, जिनमें उनके प्रदर्शन और आवाज शामिल हैं, जो उन्हें बदनाम करते हैं और उन्हें अशोभनीय हास्य का विषय बनाते हैं, जिससे उनके प्रदर्शन में उनके नैतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। सानू अपनी आवाज, गायन शैली और तकनीक, गायन व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण, गायन के तरीके और उनके चेहरे को बदलने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बनाई गई सामग्री से भी व्यथित हैं।

गोयल ने कनाडा के समकक्ष के साथ की वर्चुअल बैठक, आर्थिक साझेदारी पर दिया गया जोर

नई दिल्ली। भारत और कनाडा के बीच हाल के दिनों रिश्ते तनावपूर्ण रहे। हालांकि मार्क कार्नी के कनाडा के पीएम बनने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के बीच अहम चर्चा हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके अलावा नेताओं ने दोनों देशों के बीच भरोसे, सम्मान और संतुलन पर आधारित साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात भी कही। बैठक को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल? कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू

के साथ हुई इस बैठक के बारे में पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हमने ऐसे अवसरों पर चर्चा की जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं का लाभ उठाते हुए व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने जोर देकर कहा कि भारत-कनाडा के व्यापारिक रिश्ते आपसी सम्मान, विश्वास और संतुलन पर आधारित होने चाहिए। इस बैठक को लेकर कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने भी कहा कि वे भारत के साथ आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने

और क्लीन टेक्नोलॉजी, एआई, कृषि, और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में



नए व्यापारिक अवसरों पर काम कर रहे हैं। अब समझिए क्यों अहम है ये बातचीत?

बता दें कि 2023 में कनाडा ने भारत के साथ चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) की बातचीत को रोक दिया था। इसके पीछे कारण था कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा एक सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत पर कथित सलिपता का आरोप लगाना। भारत ने इन आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया था। हालांकि, दोनों देशों ने मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता (ईपीटीए) को लेकर बातचीत दोबारा शुरू की थी। अब तक

इस पर छह से ज़्यादा दौर की बातचीत हो चुकी है। क्या कहते हैं व्यापारिक आंकड़े, ये भी समझिए वहीं बाद अगर दोनों देशों के बीच हुए व्यापार के आंकड़े की करें तो भारत का कनाडा को निर्यात 2023-24 में 3.84 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 4.22 अरब डॉलर हो गया, जिसमें 9.88 की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं कनाडा से आयात 4.55 अरब डॉलर से घटकर 2024-25 में 4.44 अरब डॉलर रह गया, जिसमें 2.33इ की गिरावट दर्ज की गई। भारत-कनाडा के बीच रिश्तों में क्या? गौरतलब है कि कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद रविवार से नई दिल्ली की यात्रा पर आ रही हैं। माना जा रहा है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच बिगड़े रिश्तों को सुधारने की दिशा में एक और सकारात्मक कदम है।

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार स्वस्थ भारत की नींव - डॉ जी एस तोमर

झूँसी, प्रयागराज: आरोग्य भारती एवं डॉ प्रीति हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में प्रवेक कल्प के सौजन्य से ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियान के अन्तर्गत डॉ प्रीति हॉस्पिटल, झूँसी में ‘स्त्री स्वास्थ्य एवं सुपोषण’ विषय पर शनिवार 11 अक्टूबर को एक वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जी बी पंत की डायरेक्टर डॉ अर्चना सिंह जी उपस्थित रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में मोतीलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज के पूर्व शोध अधिकारी डॉ शांति चौधरी एवं त्रिवेणीपुरम विकास एवं कल्याण समिति की सचिव पर्यावरणविद् डॉ निर्मला तोमर ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अमित त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत एवं अभिन्नंदन किया।संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ प्रीति त्रिपाठी ने की। अतिथि वक्ताओं में रोटेरियन श्रीमती गीतिका अष्ठाना ने ‘सुजनात्मकता एवं स्वास्थ्य’ विषय पर अपना उद्बोधन दिया एवं अपनी काव्य रचना को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पारिवारिक दायित्व के साथ साथ हमें अपनी हॉबी को हमेशा जीवंत रखना चाहिए। कविता, गायन एवं नृत्य न केवल मन को प्रसन्नता एवं सकारात्मकता

से भरते हैं अपितु सम्पूर्ण स्वास्थ्य को भी समुन्नत करते हैं। श्रीमती मोक्षदा सिंह ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि शिक्षा केवल नौकरी नहीं स्वावलंबन के दरवाजे भी खोलती है। वनस्थली विद्यापीठ जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री लेने के बाद मैंने अपनी अभिरुचि को हमेशा जीवित रखा। यही कारण है कि मैंने मुम्बई से अपनी नौकरी छोड़ कर पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ ‘क्रस्ट कलाउड किचन’ का प्रारम्भ किया। पारम्परिक आहार में नवाचार’ विषय पर अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि पिज़्ज़ा, नूडल्स, पास्ता एवं बर्गर जैसे पाश्चात्य खाद्यमांओं की तरफ बढ़ रहे नई पीढ़ी के झुकाव को देखते हुए हमें नवाचार के माध्यम से शुद्धता एवं गुणवत्ता से अपनी पारंपरिक आहार संस्कृति में बदलाव लाने की ज़रूरत है। शुद्धता एवं पौष्टिकता को आधार बनाकर नवाचार के माध्यम से स्वदेशी एवं पारम्परिक आहार व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना हमारा दायित्व है। विशिष्ट अतिथि डॉ निर्मला तोमर ने अपने व्यक्तिगत जीवन में लिए गए दृढ़ संकल्प के माध्यम से कूड़े के अम्बार से पटे हुए पार्क को सुंदर ग्रीन पार्क में तब्दील करने की



ने बताया कि प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार हरे भरे पार्क के एक किलोमीटर की परिधि में रहनेवालों को एंजाइटी तथा

डिप्रेशन जैसे मनोरोग नहीं होते। उन्होंने बताया कि हर काम सरकार के भरोसे न छोड़कर हमें अपनी संकल्प शक्ति से भी काम लेना होगा। डॉ निर्मला

परियोजनाओं को पहुंचाना है तभी समग्र विकास संभव है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में लोकप्रिय एवं ख्याति लब्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ प्रीति त्रिपाठी ने चिकित्सा को मात्र धनार्जन का साधन न मानते हुए सेवा का सशक्त माध्यम भी बताया एवं चिकित्सा को सभी पुण्य कर्मों में श्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा झूँसी जैसे क्षेत्र में महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू सहित सभी सुविधाओं से युक्त चिकित्सालय की स्थापना के पीछे यही पुनीत उद्देश्य छिपा है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने रोगियों के प्रति करुणा एवं मैत्री का भाव स्थापित करते हुए उन्हें आवश्यक औषधियों के साथ साथ उचित खान पान की जानकारी भी साझा करूँ। कार्यक्रम के अंत में अनुराग अष्ठाना ने धन्यवाद ज्ञापित कर शांति मंत्र के साथ समापन किया। संचालन आरोग्य भारती के उपाध्यक्ष डॉ जी एस तोमर ने किया। इस अवसर पर आरोग्य भारती महानगर सचिव बृजेन्द्र श्रीवास्तव, अखिलेन्द्र सिंह, अंकुर सिंह सहित विविध क्षेत्रों से लगभग पचास पुरुष एवं महिलाएँ उपस्थित रहीं।

अयोध्या दीपोत्सव की भव्य तैयारी: 28 लाख दीयों से बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड!

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा कि शहर में नौवें दीपोत्सव के तहत अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 56 घाटों को लगभग 28 लाख दीपों से रोशन किया जाएगा। पहली बार, लक्ष्मण

संगठनों की टीमें अथक प्रयास कर रही हैं। सजावट, सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आगंतुकों के आतिथ्य सत्कार के लिए व्यापक तैयारियाँ चल रही हैं। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध



और चौधरी चरण सिंह घाटों पर लगभग डेढ़ लाख दीये जलाए जाएंगे, जबकि भजन संध्या घाट भी डेढ़ लाख दीयों से जगमगाएगी। उत्सव का मुख्य आकर्षण, राम की पैड़ी, 15-16 लाख दीयों से जगमगाएगी। पिछले वर्षों में अयोध्या के दीपोत्सव को गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। इस वर्ष, आयोजकों का लक्ष्य 28 लाख दीये जलाकर उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार, प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवी

विश्वविद्यालय में दीपोत्सव के नोडल अधिकारी प्रो. संत शरण मिश्र की देखरेख में, महोत्सव के हर पहलू की निगरानी के लिए 22 समितियों का गठन किया गया है। बयान में कहा गया है कि प्रमुख समितियों में समन्वय, अनुशासन, सुरक्षा, दीप गणना, यातायात, सच्छता, मीडिया एवं फोटोग्राफी, प्राथमिक चिकित्सा, सजावट, रंगोली, स्वयंसेवकों की पहचान पत्र, और निगरानी एवं नियंत्रण शामिल हैं।

कोलकाता में मूक-बधिर युवती से बलात्कार , एक गिरफ्तार

कोलकाता में शनिवार तड़के एक व्यक्ति ने 20 वर्षीय मूक-बधिर युवती के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक बरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कथित घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी की गई। उन्होंने बताया कि यह घटना शहर के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में नडियाल इलाके में रात करीब 12:30 बजे हुई। अधिकारी ने बताया कि महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी चिकित्सा जांच की जा रही है। उन्होने घटना का ब्यौरा



दिए बिना बताया कि विशेष सूचना के आधार पर नडियाल पुलिस थाने के अधिकारियों ने छापेमारी की और शनिवार सुबह करीब 6:35 बजे आरोपी

को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने कहा, आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और उसे बाद में स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।

भारत से रिश्ते सुधारने में लगे ट्रंप, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने की जयशंकर ने मुलाकात

वाशिंगटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को भारत में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की, जो सीनेट द्वारा उनकी नियुक्ति की पुष्टि के बाद छह दिवसीय नई दिल्ली यात्रा पर हैं। जयशंकर ने” पर पोस्ट किया आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत-पदनामित सर्जियो गोर से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत-अमेरिका संबंधों और इसके वैश्विक महत्व पर चर्चा हुई। उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, 9 से 14 अक्टूबर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान गोर के साथ प्रबंधन एवं संसाधन उप-सचिव माइकल जे. रियास भी मौजूद रहेंगे।

यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों पक्ष एक

व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और प्रौद्योगिकी एवं रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीके तलाश रहे हैं। अमेरिकी



दूतावास के अनुसार, हाल ही में भारत पहुंचे गोर बाद में औपचारिक रूप से अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी शनिवार को

गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बरणीर जायसवाल ने साझा किया विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने

और इसकी साझा प्राथमिकताओं पर उपयोगी बातचीत हुई। विदेश सचिव ने मनोनीत राजदूत गोर को उनके कार्यभार के लिए शुभकामनाएं दीं। इससे पहले, जयशंकर ने 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र के दौरान गोर से मुलाकात की थी, जहाँ दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा की थी। मुलाकात के बाद, अमेरिकी विदेश विभाग ने एक्स पर साझा किया, दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत और भारत में राजदूत नामित सर्जियो गोर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की। वे अमेरिका-भारत संबंधों की सफलता को और बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं।

गाजा विरोध में पाकिस्तान लहलुहान: पुलिस-इस्लामी समूह झड़प में 11 की मौत, तनाव गहराया

लाहौर। लाहौर में शनिवार को पुलिस और इस्लामी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के बीच हिंसक झड़पें जारी रही, क्योंकि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को राजधानी की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जहाँ वे फ़िलिस्तीन समर्थक रैली निकालने वाले थे। पंजाब पुलिस को इज़राइली गुंडे बताते हुए, तहरीक-ए-लब्बैक ने दावा किया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें उसके 11 सदस्य मारे गए और 50 से ज़्यादा घायल हो गए। सुबह से अब तक टीएलपी के 11 लोग मारे जा चुके हैं। लगातार गोलाबारी और गोलीबारी हो रही है। इज़राइल द्वारा गाजा में की गई हत्याओं

के विरोध में गुरुवार को शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन शनिवार को और तेज़ हो गया जब पुलिस ने कई जगहों पर

गए। लाहौर के आज़ादी चौक के पास झड़पें तेज़ हो गईं, जहाँ कई पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई और कई अधिकारी घायल हो गए।

कई इलाकों में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए, शिपिंग कंटेनर रख दिए और यहाँ तक कि खाइयाँ भी खोद दीं ताकि टीएलपी के हजारों प्रदर्शनकारियों को, जिनका नेतृत्व सांठन के प्रमुख साद रिज़वी कर रहे थे, इस्लामाबाद की ओर अमेरिकी दूतावास के पास प्रदर्शन के लिए जाने से

रोका जा सके। लाहौर इस्लामाबाद से लगभग 370 किलोमीटर दूर है। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को बड़ी भीड़-भाड़ से बचने और अपने आस-पास के वातावरण के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है।

प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें द डोन की रिपोर्ट के अनुसार दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो

यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर रूसी हमले से कीव में बाधित बिजली आपूर्ति बहाल

कीव। यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर रूस द्वारा बड़े हमलों के कारण देश के अधिकतर हिस्सों में बिजली गूल होने के एक दिन बाद शनिवार को कीव में 8,00,000 से अधिक निवासियों के लिए बिजली आपूर्ति

रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में शुक्रवार तड़के कीव में कम से कम 20 हिस्सों में बिजली गूल होने के एक दिन बाद शनिवार को कीव में 8,00,000 से अधिक निवासियों के लिए बिजली आपूर्ति



बहाल कर दी गई। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी 'डेट्रीईक' ने शनिवार को कहा कि बिजली आपूर्ति बहाल करने का मुख्य कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन शुक्रवार के रूसी हमलों के कारण यूक्रेनी राजधानी में मामूली स्तर पर कटौती अब भी जारी है।

यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने इस हमलों को यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर “सबसे बड़े केंद्रित हमलों में से एक” बताया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि हमलों का निशाना यूक्रेन की सेना को बिजली आपूर्ति करने वाले ऊर्जा बुनियादे ढांचे थे।

Facebook: <https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044>

Twitter:

<https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08>

Mobile No:

7007837917